स्वतंत्रता आंदोलन में प्रिंट मीडिया

डॉ शशि रानी
एसोसिएट प्रोफेसर
डॉ.भीमरावअम्बेडकरकॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय

सार

किसी भी देश को स्वतंत्रता प्राप्ति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करती है। संचार या मीडिया किसी भी समाज को लक्ष्य प्राप्ति हेतु उन कारकों को समन्वित करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लंबे संघर्ष में पत्रकारिता ने अपनी स्वभूमि को भली-भांति निभाया है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मैराथन संघर्ष में संचार का अभाव प्रमुख समस्या थी। पत्रकारिता ने इस अभावको भरते हुए लोगों में देशभक्तिकी भावनाजगा कर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भारतीयों का मार्गदर्शन कर स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्गप्रशस्तकिया। पत्र पत्रिकाएं जनता से संवाद का माध्यम बनी।नेताओं ने अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करके उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता की भावना को दबाने और स्वतंत्रता सेनानियों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने के लिए मीडिया की अद्भुत शक्ति को पहचानते हुए ब्रिटिश सरकार ने पत्रकारिता के प्रारंभ से ही विविधप्रतिबंध लगाए थे। पत्रकारों नेसरकार के इनकृत्योंके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस शोध पत्र में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में पत्रकारों के योगदान का विशेष विश्लेषण किया गया है जिन्होंने देशवासियों को शिक्षित और जागरूक करने में अहम भूमिका का निर्वहन किया ।

1. परिचय

1857 कासिपाही विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध था। पहली बार मीडिया के बिना बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में नागरिकों सहित सिपॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भाग लिया था । संचार और प्रचार की कमी के कारण आंदोलन अपने चरम पर नहीं पहुंच सका। उसके बाद राजाराममोहन राय, दादाभाई नौरोजी और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे कई समाज सुधारकों ने राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने और समाज से अंधविश्वासों को खत्म करने में मदद की।

1857 में'पजामेआजादी'में हिंदी और उर्दू भाषा में लेख प्रकाशित किए गए जिनका उद्देश्य लोगों को कंपनी के शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना था। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। उसी समय हिंदी भाषा में हिंदी दैनिक 'समाचार सुधा वर्षण', उर्दू - फारसी में'दूरबीन और सुल्तान –उल– अकबर समाचार पत्रों को भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किए गए 'गला घोटू' अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि इनमें बहादुर शाह जफर के अंग्रेजो के खिलाफ फरमान को छापा गया था। (रणदिवे.,और अन्य 1984)।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र की भूमिका:

स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ ऐसे समाचार पत्र थे। जिन्होंने लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने और सामाजिक सुधार करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदी देशभक्त ऐसाहीपत्र था जो 1853 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा शुरू किया गया था, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी के संपादकीय में प्रसिद्ध हुआ। लाला हरदयाल

के नेतृत्व में गदर पार्टी के लिए गदर नाम की पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई। दिन-ब-दिन यह अखबार उर्दू, पंजाबी, मराठी, हिंदी, गुजराती और यहां तक कि अंग्रेजी में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में लोकप्रिय हो गया। यह पहला विदेश में भारतीय अखबार था जिसके कारण अमेरिका में लाला हरदयाल को अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तार किया था ।

बंगाल गजट उन लोकप्रिय समाचार पत्रों में से एक है जो स्वतंत्रता से पहले प्रकाशित हुआ था। यह पत्र 29 जनवरी 1780 कोजेम्स ऑगस्टस हिक्की नेशुरूकिया। यह समाचार पत्र इतना लोकप्रिय था कि ब्रिटिश काल के दौरान इसे पहले क्रांतिकारी समाचार पत्र के रूप में जाना जाता था।

1.1 साहित्य समीक्षा

पांडे., (2016),के अनुसार, 1870 से 1918 के दौरान प्रतिष्ठित और निडर पत्रकारों के संपादकत्वइन वर्षों के दौरानशक्तिशाली समाचार पत्रों का उदय हुआ। द हिंदू, स्वदेश मित्रन(जी सुब्रमण्यम अय्यर), केसरी और मराठा (बाल गंगाधर तिलक), द बंगाली (सुरेंद्रनाथ बनर्जी), अमृत बाजार पत्रिका (हेमेंद्र कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के संयुक्त प्रयास से), सुधारक (गणेश आगरकर), इंडियन मिरर (मनमोहन घोषऔर देवेन्द्रनाथ टैगोर), वॉइस ऑफ इंडिया (दादाभाई नौरोजी), हिंदुस्तानीऔर एडवोकेट(जेपी वर्मा)। पंजाब में दी ट्रिब्यून और अखबार– ए– आमबॉम्बेमें इंदु प्रकाश ,ज्ञान प्रकाश, गुजराती और बंगाली में सोम प्रकाश, बंगवासी ने विशेष पहचान बनाई ।

प्रेस मुख्य राजनीतिक कार्यों जैसे राजनीतिक प्रचार, शिक्षा, और राष्ट्रवादी विचारधारा के गठन और प्रचार के लिए राष्ट्रवादी जनमत को जगाने, प्रशिक्षित करने, लामबंद करने और समेकित करने के लिए प्रमुख साधन था। यहाँ तक कि राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य भी इन वर्षों में मुख्यतः प्रेस के माध्यम से संपन्न हुआ। इसमें जो संकल्प लिए गए और उसकी बैठकों की कार्यवाही का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। उस समय के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक विवादों को प्रेस के माध्यम से चलाया जाता था।

- 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से लगभग एक तिहाई पत्रकार थे। वास्तव में, भारत में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं के पास या तो एक समाचार पत्र था या वे किसी न किसी के लिए अपने लेखन का योगदान दे रहे थे। अखबारों का प्रचलन केवल शहरों या बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था। दूर-दराज के गांवों में अखबार पहुंचते थे।धीरे-धीरे पूरे देश में पुस्तकालयों का चलन शुरू हो गया। एक ही अखबार को स्थानीय 'लाइब्रेरी' का केंद्र बनाया गया। मुख्य संपत्ति एक टेबल, एक बेंच या दो या चारपाई हुआ करती थी। समाचार या संपादकीय टिप्पणी के हर अंश को पढ़ा या सुना जाएगा और अच्छी तरह से चर्चा की जाएगी। समाचार पत्रों को राजनीतिक शिक्षक के रूप में माना जाने लगा और उन्हें पढ़ना या चर्चा करना राजनीतिक भागीदारी का एक रूप बन गया । राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनके दौरान समाचार पत्रों को व्यावसायिक इरादों से नहीं बल्कि राष्ट्रीय या सार्वजनिक सेवा के रूप में प्रकाशित किया गया था। उन्हें समृद्ध, जागरूक परोपकारी लोगों द्वारा संरक्षण और वित्तपोषित किया गया था।
- इसने सरकार के लिए विपक्ष की संस्था की भूमिका निभाई। एक विद्वेष के रूप में, लगभग हर कार्य और हर नीति जिसके साथ सरकार आगे बढ़ी, की बेरहमी से आलोचना की गई। इस संबंध में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने मार्च 1886 में लिखा, 'दिन-ब-दिन, सैकड़ों तेज-तर्रार बाबु अपने अंग्रेजी उत्पीड़कों के खिलाफ बहुत तीखे और प्रभावी व्यंग्य में अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं।' मई में फिर से वे लिखते हैं, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन पत्रों को पढ़ने वालों के मन में कोई संदेह नहीं है। . . एक ईमानदार विश्वास है कि हम सभी सामान्य रूप से मानव जाति के और विशेष रूप से भारत के दुश्मन हैं।'

- 1870 से भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में कहा गया है कि 'जो कोई भी ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है' उसे आजीवन कारावास या तीन साल तक की कैद या किसी भी अवधि के लिए दंडित किया जाना था।
- भारतीय पत्रकारों ने धारा 124 ए के बाहर रहने के लिए हथकंडे अपनाए। वे लंदन स्थित समाजवादी और आयरिश समाचार पत्रों या कट्टरपंथी ब्रिटिश नागरिकों के पत्र से साम्राज्यवाद विरोधी उद्धरण प्रकाशित करेंगे। हिन्दोस्तानी (अंग्रेजों) की सरकार, अपमान करनेवाले अंग्रेजों को भी दण्डित किये बिना, भारतीयों के विरुद्ध कार्यवाही करने में उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती थी।
- इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक ही बैठक में भारतीय भाषा के अखबारों के खिलाफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। अधिनियम ने एक अखबार के प्रिंटिंग प्रेस, कागज और अन्य सामग्रियों को जब्त करने का आदेश दिया, अगर सरकार को लगता है कि यह भड़काऊ सामग्री प्रकाशित कर रहा है और सरकार की किसी भी चेतावनी का उल्लंघन किया है (किब्रिया.,और अन्य 1999)।

राष्ट्रवादी सार्वजनिक निकायों और प्रेस ने इस अधिनियम के खिलाफ अभियान चलाया। आखिरकार, इसे 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त करना पड़ा। सबसे प्रमुख पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और कांग्रेसियों में से एक बाल गंगाधर तिलक थे। उनके पास दो समाचार पत्र थे, एक मराठी में जिसे केसरी कहा जाता था और दूसरा अंग्रेजी में जिसे महरट्टा कहा जाता था। उनके बढ़ते आंदोलन ने कई नेताओं को जमा किया और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसलिए उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। इन गतिविधियों के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चला। लेकिन भारतीय प्रेस ने अपनी भूमिका कम नहीं होने दी।

1.2 अनुसंधान अंतराल

शोध अपने आप में किसी चीज़ को नए तरीकों से प्रस्तुत करने, पुराने विचारों को एक नवीन तरीके से पुन: प्रस्तुत करने, या एक नई अवधारणा की खोज करने का एक अनूठा तरीका है। प्रत्येक शोधकर्ता अपने शोध कार्य को दूसरों से अलग बनाता है। इस प्रकार अनुसंधान अंतराल उन विचारों के विस्तार में एक सेतु के रूप में कार्य करता है जिन पर पहले चर्चा नहीं की गई है। इस शोध पत्र में शोधकर्ता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मीडिया की भूमिका से संबंधित कई घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से लिया है जोइसे अन्य शोध पत्रों से अलग बनाता है। इसके अलावा, इस शोध पत्र में, शोधकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरानब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए सभी प्रेस अधिनियमों को समझाया है जो अन्य शोध पत्रों में वर्णित नहीं है ।

1.3 अनुसंधान का प्रश्न

1. ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार अनेक अधिनियमों को लागू करके प्रिंट मीडिया या समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया?
2. राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक आदि समाज सुधारकों ने भारत के नागरिकों को मीडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे प्रेरित किया?

1.4 अनुसंधान के उद्देश्य

- स्वतंत्रता आंदोलन में प्रिंट मीडिया की भूमिका जानना।
- समाज सुधार में मीडिया की भूमिका जानना।
- 1780 के बाद प्रिंट मीडिया के विभिन्न चरणों को अध्ययनकरना।
- भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत करने वाले समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक आदि के बारे में जानना।

1.5 दायरा और सीमाएं

किसी भी शोध के लिए हालांकि प्राथमिक या माध्यमिक सीमा एक प्रासंगिक हिस्सा है जिसका शोधकर्ता ध्यान रखता है। शोध कार्य के माध्यम से श्रोताओं के पास जाते समय शोधकर्ता को गलती करने से बचने के लिए हर एक फाइल पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चूंकियह शोध-पत्र यद्यपि द्वितीयक शोध-पत्र है, अतः शोधार्थी ने इस विषय से संबंधित आँकड़े ढूँढने और एकत्रित करने में काफी समय लगाया है। शोधकर्ता ने डेटा एकत्र करते समय स्रोत की प्रामाणिकता और उपयुक्तता पूरा ध्यान रखा है।अन्य सीमाएं यह हैं कि निष्कर्ष का सांख्यिकीय रूप से उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रकृति में वर्णनात्मक है।

2. अनुसंधान क्रियाविधि

2.1 अनुसंधान विधि

शोध पत्र के लिए, शोध पद्धतियाँ आवश्यक कदम हैं जो अनुसंधान के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। इस शोध पत्र में, शोधकर्ता ने भारत के नागरिक को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रिंट मीडिया या समाचार पत्रों के महत्व का विश्लेषण करने के लिए माध्यमिक शोध पद्धति का उपयोग किया है। इस शोध पत्र में शोधार्थी ने शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने और व्यापक विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। शोधकर्ता ने लगभग 25 पत्रिकाएँ ली हैं और उनमें से 5-6 पत्रों की चर्चा साहित्य समीक्षा में की गई है।

2.2 अनुसंधान दृष्टिकोण

अनुसंधान दृष्टिकोण शोधकर्ता के लिए एक प्रारुप के रूप में कार्य करता है जो डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण प्रक्रियाओं में पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। जिससे शोधकर्ता कोअपने शोध उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए जानकारी एकत्र करने की दिशा मिलती है। इस प्रकार यहाँ शोधकर्ता ने शोध प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने के लिए अनेक पत्रोंका व्यवस्थित तरीके अध्ययन क्या है। पत्र प्रकृति में काफी वर्णनात्मक और सूचनात्मक हैं।

2.3 अध्ययन का विश्लेषण

प्रश्न - 1

प्रेस को नियंत्रण में लाने के लिए गवर्नर-जनरल द्वारा कड़े नियम जारी किए गए। 13 मई 1799 के एक विनियमन में कहा गया है कि कोई भी पेपर तब तक प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसका पहले निरीक्षण नहीं किया गया था सरकार के सचिव या उस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा।"

"सरकार या उसके किसी अधिकारी के आचरण के संबंध में सभी टिप्पणियों के प्रकाशन को रोकने के लिए आधिकारिक सेंसर था। प्रेस को सार्वजनिक ऋण की स्थिति या ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व पर कोई टिप्पणी करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।" वेलेस्ली ने भारतीय प्रेस को "पहले परिमाण की बुराई" के रूप में माना और यहां तक कि एक आधिकारिक राजपत्र की स्थापना को प्रचार प्रसार के लिए एक काउंटरब्लास्ट के रूप में माना (कैसानोवा.,और अन्य 2007) ।

"लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने के दौरान, प्रेस की आधिकारिक सेंसरशिप हटा दी गई थी और इसे संपादकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ सामान्य नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हेस्टिंग्स ने संपादकों को केवल एक सामान्य चेतावनी दी थी कि वे उन विषयों पर चर्चा न करें जो सरकार के अधिकार को प्रभावित कर

सकते हैं या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हालाँकि, हेस्टिंग्स की उदार नीति घर में निदेशकों के लिए स्वीकार्य नहीं थी और जैसे ही उन्होंने भारत छोड़ा, सेंसरशिप फिर से शुरू की गई।

"भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की अनुमति देने की समझदारी पर बहुत शुरुआती समय से ही कई अंग्रेजी प्रशासकों ने सवाल उठाया था। एलफिंस्टन का मानना था कि निरंकुश शासन वाले देश में स्वतंत्र प्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्वतंत्र प्रेस को स्वतंत्र संस्थाओं का स्वाभाविक सहवर्ती होना चाहिए। एलफिंस्टन ने जोर देकर कहा कि इस देश में हमारी सरकार कभी भी किसी भी अर्थ में लोकप्रिय सरकार नहीं हो सकती है। प्रिंटिंग प्रेस को "सभी ज्ञान के वाहन" के रूप में बंद कर दिया गया है। "लॉर्ड कैनिंग प्रेस के शत्रुतापूर्ण रवैये पर अत्यधिक क्रोधित थे। 1857 में, कैनिंग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना को विनियमित करने और इसके संचलन को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। मुद्रित किताबें और कागज। सर जॉर्ज कैंपबेल ने अपनी राय व्यक्त की कि एक पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस सरकार के एक निरंकुश रूप के साथ असंगत है, भले ही वह एक पितृ निरंकुशता हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव और देश में राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार ने एक नारा दिया अपने विशेषाधिकारों और अधिकारों के लिए प्रेस के आंदोलन को गति प्रदान करना (रणदिवे.,और अन्य 2008)।

"अक्टूबर 1889 में, सरकार ने आधिकारिक दस्तावेजों और सूचनाओं के प्रकटीकरण को रोकने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया। सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में गोखले और तिलक जैसे नेताओं के आगमन ने भारतीय प्रेस के कारण को मजबूत किया (सोनवलकर., और अन्य 2002)। 1910 में, सरकार ने भारतीय प्रेस अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को सरकार को सुरक्षा जमा करनी चाहिए। जब महान युद्ध छिड़ गया, तो प्रेस की सेंसरशिप अधिक जोरदार हो गई। सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1913) और भारत रक्षा अधिनियम (1914) पारित किया था, जिसने कार्यपालिका को भारी शक्तियाँ प्रदान की थीं (शक्तिवेल., और अन्य 1999)।"

1910 के भारतीय प्रेस अधिनियम की कड़ी आलोचना हुई। आलोचकों ने इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार विरोधी लेखन को दबाने के लिए एक सुविधाजनक हथियार के रूप में माना। आंध्र केसरी, कृष्णा पत्रिका, बाजा केरलम, इंडियन पैट्रियट, द इंडियन रिव्यू, विजया, देसा बक्टन, स्वदेशमित्रन और अन्य राष्ट्रवादी प्रेस जैसे समाचार पत्रों ने अधिनियम के कठोर प्रावधानों का उल्लेख किया। प्रेस ने अधिनियम की तुलना डैमोकल्स की तलवार से की और कहा कि अधिनियम ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया।

प्रश्न-2

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंनेपत्रकार और संपादकके रूपमेंअपने योगदान से जनता को भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का मार्ग प्रशस्त किया। राजा राम मोहन राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष और सुब्रमण्यम अय्यर कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने भारतीय जनता का मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध पत्रकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सक्रिय भारतीय की भूमिका निभाई।

पश्चिम बंगाल के राधा नगर गांव में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए राजा राम मोहन रॉय ने अपनी मातृभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और बंगाली जैसी विभिन्न भाषाओं पर बहुत मजबूत आदेश और दक्षता हासिल की। नेहरू ने उन्हें भारतीय प्रेस का संस्थापक कहा। भारतीय पत्रकारिता में उनका योगदान मुख्य रूप से स्वतंत्र प्रेस के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई में निहित है। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। उन्होंने 1821 में कलकत्ता में "संवाद कौमुदी", "मून ऑफ इंटेलिजेंस" नामक एक पत्रिका की स्थापना की, उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा वेदांत दर्शन पर हमलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1822 में फ़ारसी भाषा में एक समाचार पत्र "मिरात उल अकबर", समाचार दर्पण भी शुरू किया, लेकिन प्रेस विनियम अधिनियम 1823 के विरोध में बंद कर दिया। यह मुगल साम्राज्य का एक आधिकारिक समाचार पत्र था। हर शुक्रवार को प्रकाशित होता था।

इस साप्ताहिक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न घटनाओं को उचित स्थान और अधिक कवरेज दिया। उन्होंने धार्मिक प्रचार का विरोध करने के लिए एक धार्मिक पत्रिका, एक ब्राह्मणवादी पत्रिका भी निकाली । "द इन्क्वायरर", और ज्ञान औनेशिन", जो राम मोहन राय के साथ निकटता से जुड़े थे, प्रगतिशील हिंदू पत्रकारिता के स्कूल का प्रतिनिधित्व करते थे, जो 1891 तक बंगाल में इस क्षेत्र पर हावी था। उन्होंने 1828 में कलकत्ता में "ब्रह्मो समाज" की स्थापना की।

शिशिर कुमार घोष एक और हस्ताक्षर थे जिनके पत्रकारिता में योगदान ने ब्रिटिश राज की ताकत की नींव हिला दी। उन्होंने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ बुद्धिमत्ता दृढ़ता औरसाहस का परिचय दिया था। इस तथ्य के बावजूद कि 18 वीं शताब्दी में मीडिया अभी भी अधर में था। शिशिर ने 20 फरवरी 1868 को अपनी मां अमृतमयी देवी के नाम पर अमृता बाजार पत्रिका शुरू की। अखबार शुरू करने का मुख्य कारण नील व्यापारियों द्वारा शोषित किसानों केपक्षमेंखड़े होना और संघर्ष करना था। प्लेग के अचानक फैलने के कारण अमृत बाजार समाचार पत्र को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया औरअंग्रेजी और बंगाली केइस द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशन नेसमाचार और विचारों के माध्यम से देश की सेवा की।

3. परिणाम और निष्कर्ष

भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के समय प्रेस का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था बल्कि स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मूल्यों के बारे में भारत के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना था। स्वतंत्रता-पूर्व के दिनों में, प्रेस राष्ट्रवादी हो गया और लोगों के बीच इसकी व्यापक पहुंच और व्यापक क्षितिज था। इसने देश में प्रसिद्ध पुस्तकालय आंदोलन को भी प्रेरित किया। पुस्तकालय आंदोलन केवल शहरों और कस्बों तक ही सीमित नहीं था बल्कि कुछ दूरदराज के गांवों तक भी था जहां प्रत्येक नागरिक को समाचार सामग्री संपादकीय, लेख और विभिन्न अन्य कॉलम पढ़ने और उन पर पूरी तरह से चर्चा करने का मौका मिलता था। इसने भारत के नागरिकों में राजनीतिक चेतना जगाने में मदद की जो बाद में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी राजनीतिक भागीदारी में बदल गई।

1900 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जैसे ही राष्ट्रवादी आंदोलन ने जोर पकड़ा कई प्रमुख समाचार पत्र संपादक प्रमुख नेताओं के रूप में थे । ब्रिटिश सरकार ने एक के बाद एक अधिनियम को लागू करते हुए प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1911 के प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, 1910 के प्रेस एक्ट और 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की तरह। पारित अधिनियमों में सबसे विनाशकारी 1910 का प्रेस अधिनियम था, जिसने 1,000 से अधिक समाचार पत्रों को अभियोजन के तहत लाया और प्रतिभूतियों और ज़ब्ती के रूप में 5 लाख रुपये की भारी राशि रखी गई।

राज के अंतिम दशकों में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी ने नमक मार्च निकाला था, 1931 में प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम पारित किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे मजबूत किया गया था। अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबाने की शक्ति दी और बाद में कांग्रेस की सभी बातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसका एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जैसे ही युद्ध छिड़ गया और भारतीयों को गड़बड़ी में शामिल किया गया, भारत में प्रेस ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उद्देश्य से अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादकों के सम्मेलन का गठन किया।

ब्रिटिश राज के अंत तक, हालांकि, पूर्व-सेंसरशिप जारी रही। यह 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान सबसे अधिक स्पष्ट था, जिसे विशेष रूप से अमृत बाजार पत्रिका द्वारा रिपोर्ट किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को देश को यह बताने से रोक दिया कि उसे अकाल के बारे में बात करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।प्रेस ने भूमिगत कागजात, रेडियो, कला और भित्तिचित्रों का उपयोग करके अपना प्रतिरोध जारी रखा। यह तब तक जारी रहा जब तक अंग्रेजों ने अंततः भारत को छोड़ नहीं दिया।

4. संदर्भ

अयंगर, ए.एस. (2001)। प्रेस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका: गांधीवादी युग के दौरान। एपीएच प्रकाशन।
सोनवलकर, पी. (2002)। भारतीय प्रेस का 'मर्डोनाइज़ेशन': बाय-लाइन से बॉटम-लाइन तक। मीडिया, संस्कृति uy और समाज, 24(6), 821-834।
किब्रिया, एम। (1999)। गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। एपीएच प्रकाशन।
पांडे, जी.पी. (2014)। 1857 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉक्टरेट शोध प्रबंध)।
शक्तिवेल, आर। (2015)। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका-भारत की एक केस स्टडी (समाचार पत्र)। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आईजेएएसआरडी), 2(4), 111-118।
रणदिवे, बी. टी. (1986)। भारत का स्वतंत्रता संग्राम। सामाजिक वैज्ञानिक, 81-126।
रणदिवे, बी. टी. (1984)। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कम्युनिस्टों द्वारा निभाई गई भूमिका। सामाजिक वैज्ञानिक, 3-32।
कैसानोवा, सी। (2007)। भ्रष्टाचार के निर्धारक। प्रेस स्वतंत्रता की भूमिका।
मित्तल, एस. के. (1978)। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ कॉलेज की भूमिका। सामाजिक वैज्ञानिक, 35-56।
कौर, ए. पी. समकालीन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता: मुद्दे और चुनौतियां।
ब्रह्मानंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तर प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता, 1986
जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, 2011
डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र, हिंदी पत्रकारिकता